राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 174

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, सोमवार, 2 दिसंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

गांगुली का कार्यकाल 2024 तक बढ़ाने की तैयारी

>> 14

सरोकार

पहाड़ों को प्रदूषण से आजादी दे रहे कौशल

मनाली : हिमाचल प्रदेश के मनाली के ब्राण गांव निवासी पर्वतारोही कौशल भारद्वाज ने पर्यटकों को सैर कराने के साथ ही पहाड़ों को प्रदूषण से आजादी दिलाने का जिम्मा उठाया है। कौशल ने चोटियों से कई गाड़ियों में कचरा भरकर कूड़ा संयंत्र पहुंचाया। उनके इस प्रयास में कई संस्थाएं भी जुड़ गई हैं। (पेज-11)

जागरण विशेष

कश्मीर में फुटबॉल ने गिराई मजहब की दीवार

जम्मू : फुटबॉल के खेल ने कश्मीर में हिंदू-मुस्लिम एकता की नई इबारत लिखी है। कश्मीरी मुस्लिम शमीम मेराज व पंडित संदीप चट्टू ने विपरीत हालात में मिलकर रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब का गठन किया, जिसने कश्मीर को नई पहचान दी है। (पेज-10)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

बालिग दुल्हन के नाबालिग दूल्हे को सुप्रीम कोर्ट से राहत

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह से संबंधित एक मामले पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर दूल्हे पर दर्ज हुए केस को रद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने आदेश देकर गंभीर गलती की है, क्योंकि शादी के वक्त लड़के की उम्र 17 वर्ष थी, इसलिए उस पर बाल विवाह कानून की धारा नौ के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 5

दरिंदों को सजा दिलाने को फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई

हैदराबाद : महिला पशु चिकित्सक की दुष्कर्म के बाद बेरहमी से मार देने की घटना पर देश भर में उबाल कम नहीं हुआ है। घटना के तीन दिन बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने भी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने मामले की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का आदेश दिया है, ताकि जल्द से जल्द दरिंदों को सजा दिलाई जा सके।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

नवंबर में जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ के पार

नई दिल्ली : देश में नवंबर में जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) संग्रह की राशि 1,03,492 करोड़ रुपये पहुंच गई। नवंबर में जीएसटी संग्रह की वृद्धि दर छह फीसद है। इसे अर्थव्यवस्था के लिए पूरी राहत नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर अक्टूबर में मिले तेजी के संकेत नवंबर में हवा हो गए हैं।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक फिर सड़कों पर उतरे

हांगकांग : हांगकांग में लोकतंत्र की मांग कर रहे आंदोलनकारी रविवार को फिर सड़क पर उतरे। निकाय चुनावों में मिली भारी सफलता और अमेरिका द्वारा समर्थन में बनाए गए कानून से आंदोलनकारी जोश से भरे हुए थे। एक हजार से ज्यादा लोगों अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पहुंचकर आभार जताया। पुलिस ने इन्हें तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े।

जांच आयोग का निष्कर्ष-नक्सल ऑपरेशन में मारे गए थे 17 ग्रामीण

नईदुनिया, जगदलपुर

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सारकेगुड़ा कांड की जांच कर रहे न्यायिक आयोग की रिपोर्ट कथित रूप से लीक हो गई है। दावा किया जा रहा है कि रिपोर्ट में केंद्रीय आरक्षी पुलिस बल (सीआरपीएफ) और छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों ने नक्सल ऑपरेशन के नाम पर 17 ग्रामीणों को एकतरफा फायरिंग में मार डाला था। ग्रामीण निहत्थे थे। मृतकों में सात नाबालिग भी शामिल थे। रिपोर्ट विधान सभा के पटल पर रखे जाने से पहले लीक होने की सूचना से छत्तीसगढ़ सरकार सकते में है।

यह घटना बीजापुर जिले के बासागुड़ा स्थित सारकेगुड़ा गांव में 28 और 29 जून 2012 को हुई थी। पहले दिन 16 ग्रामीणों और दूसरे दिन एक ग्रामीण पुलिस फायरिंग में मारे गए थे। घटना में एक जवान भी मारा गया था और छह जवान घायल हुए थे। पुलिस मारे गए ग्रामीणों को नक्सली बता रही थी, लेकिन ग्रामीण विरोध में उतर आए थे। जुलाई 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह सरकार ने इस मुठभेड़ की न्यायिक जांच कराने के लिए आयोग के गठन का फैसला लिया था। 11 जुलाई 2012 को जबलपुर हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश वीके अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोग ने जांच शुरू की। रिपोर्ट 17 अक्टूबर 2019 को शासन को सौंप दी गई है।

सुरक्षाबलों की गोलीबारी आत्मरक्षा के लिए नहीं थी: आयोग ने रिपोर्ट के निष्कर्ष में बताया है कि सुरक्षाबलों ने आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाई थी। छह मृतकों के सिर पर गोली लगी थी। 10 मृतकों की पीठ पर रायफल की बट से चोट पाई गई थी। वहीं, जवान की मौत भी सुरक्षा बलों की फायरिंग में हुई थी।

घने जंगल नहीं, खुले मैदान में जुटे थे ग्रामीण : दावा है कि जांच आयोग के अनुसार सारकेगुड़ा, कोत्तागुड़ा और राजपेंटा के ग्रामीण 28 जून 2012 की देर शाम घने जंगल नहीं खुले मैदान में बैठक कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय सुरक्षा बल और राज्य पुलिस के जवानों ने आयोग के समक्ष दावा किया था कि बैठक नक्सलियों की मौजूदगी में घने जंगल में हो रही थी। जिसे आयोग ने नहीं माना है। हालांकि आयोग ने ग्रामीणों की भी इस बात से सहमति नहीं जताई है कि बैठक घटना के अगले दिन होने वाले बीज पंडुम त्योहार के लिए बुलाई गई थी।

30 लोगों की हुई थी गवाही : आयोग ने पीड़ित पक्ष के 17, फोर्स और अन्य 13 लोगों को मिलाकर कुल 30 गवाहों का बयान दर्ज किया है। आयोग के गठन के बाद कई महीनों तक पीड़ित परिवारों से कोई भी बयान दर्ज कराने नहीं आया थे। बाद में पीड़ितों की ओर से गवाहों ने शपथ पत्र देकर बयान दर्ज कराया था।

विधानसभा की अवमानना : रिपोर्ट लीक होने पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि यह विधानसभा की अवमानना है। विधानसभा चलने के दौरान इस तरह रिपोर्ट को लीक करके सरकार ने बड़ा अपराध किया है। उन्होंने इसकी जांच कराए जाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। इस विषय में वह सोमवार को विधानसभा में प्रश्न उठाएंगे।

जो कहना है सदन में कहेंगे : आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि आयोग की रिपोर्ट सोमवार को सदन में रखी जाएगी। ऐसे में जो भी कहना है, वह सदन में ही कहेंगे।

2012 में छत्तीसगढ़ में हुई मुठभेड़ पर उठे सवाल

- बीजापुर में हुई थी घटना, आज सदन में पेश की जानी है आयोग की रिपोर्ट
- सीआरपीएफ ने कहा था कि नक्सलियों की मौजूदगी में हो रही थी बैठक

यह तस्वीर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में वर्ष 2012 के सारकेगुड़ा में ऑपरेशन के दौरान मारे गए ग्रामीणों की है। मृतकों को नक्सली बताया गया था, किंतु जांच में निष्कर्ष निकला है कि सभी मृतक ग्रामीण थे (फाइल फोटो)। नई दुनिया

जस्टिस अग्रवाल आयोग की रिपोर्ट के अहम बिंदु

- ग्रामीणों ने फोर्स पर हमला नहीं किया था। सुरक्षाबलों ने शुरू में कहा था कि बैठक में शामिल लोगों ने हमला किया, डीआइजी ने कहा, उन्होंने बैठक स्थल की दिशा से गोली आते नहीं देखी
- फोर्स को गाइड ने कुछ संदिग्ध आवाज सुनने की बात बताई तो जवानों को हमले की आशंका हुई। इसी कारण उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी
- सीआरपीएफ और राज्य पुलिस ने कहा था कि कार्रवाई के दौरान सुरक्षाबलों के छह जवान भी घायल हुए
- हालांकि जख्म के निशान इस बात को साबित करते हैं कि गोली दूरी से नहीं चलाई गई थी
- अंधेरे की वजह से सुरक्षाबलों के जवानों की गोली ही साथियों को लगने की आशंका है

प्रदूषण पर नहीं चेते राज्य

ढुलमुल रवैया ▶ 23 राज्यों को दिया गया पैसा व प्लान, नहीं किया काम

120 दिन में करना था अमल, संसद में उठे सवाल तो सामने आई हकीकत

अरविंद पांडेय, नई दिल्ली

वायु प्रदूषण का बढ़ता स्तर भले ही जानलेवा बना हुआ है, लेकिन राज्यों का रवैया इसे लेकर ढुलमुल है। यह स्थिति तब है, जब केंद्र इससे निपटने को 23 राज्यों को पैसा और कार्ययोजना दोनों मुहैया करा चुकी है। बावजूद इसके अब तक किसी राज्य ने कोई काम शुरू नहीं किया है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि एक साल के अंदर केंद्र से भी कोई पूछताछ नहीं हुई।

राज्यों को जो प्लान दिया गया था, वह करीब 132 बिंदुओं का था। इसमें वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर रोकथाम से लेकर धूल और उद्योगों से होने वाले प्रदूषण, बायोमास जलाने से होने वाले प्रदूषण आदि से निपटने की पूरी योजना है। जो प्लान दिया गया है, उनमें अधिकतम 120 दिन में सभी कामों पर अमल करना था, लेकिन इस बीच पत्ता तक नहीं हिला।

मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक राज्यों के रवैये का पता तब चला, जब संसद में उठ रहे सवालों के बीच राज्यों से वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी ली गई। इस दौरान ज्यादातर राज्यों ने अब तक योजना के तहत कोई भी काम नहीं किया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्टों के आधार पर शहरों का चयन : वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना (एनसीएपी) बनाई है। 23 राज्यों के 122 शहरों को इसमें शामिल किया है। इन शहरों का चयन विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2014 और 2018 की उन रिपोर्टों के आधार पर किया गया है, जिनमें वायु प्रदूषण के चलते लोगों की हो रही मौत और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर चेताया गया था। इन शहरों में वायु की गुणवत्ता भी मानकों के अनुरूप नहीं है। बता दें कि स्वच्छ वायु की गुणवत्ता का निर्धारण पीएम-10 और पीएम 2.5 के स्तर पर होता है। जिसमें पीएम-10 का स्तर 100 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर से नीचे और पीएम-2.5 का स्तर 60 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर से कम होना चाहिए।

ये प्रमुख शहर हैं योजना में शामिल : राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना में दिल्ली, मुंबई, कानपुर, लखनऊ, चंडीगढ़, वाराणसी, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद, पटना, रायपुर, विजयवाड़ा, सूरत, भोपाल, ग्वालियर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, आगरा, प्रयागराज, आदि शहर शामिल हैं। इस योजना में उत्तर प्रदेश के कुल 15 शहरों को, पंजाब के नौ, मध्य प्रदेश के छह, बिहार के तीन और झारखंड के एक (धनबाद) शहर को शामिल किया गया है।

किस शहर को मिला कितना पैसा

- योजना के तहत 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले 28 शहरों को 10-10 करोड़ रुपये दिए गए
- पांच से 10 लाख की आबादी वाले प्रत्येक शहर को केंद्र सरकार ने 20 लाख रुपये दिए
- पांच लाख से कम आबादी वाले प्रत्येक शहर को 10 लाख रुपये दिए गए।
- 2024 तक पीएम-10 और पीएम-2.5 के स्तर को 20 से 30 फीसद तक कम करने का दिया गया है लक्ष्य

दिल्ली-एनसीआर की स्थिति प्रदूषण के लिहाज से खराब

नई दिल्ली : दिल्ली-एनसीआर की स्थिति प्रदूषण के लिहाज से बेहद खराब है। यहां प्रदूषण के कारकों में कुदरती धूल, कोहरा और मंद हवा ही नहीं बल्कि मानव निर्मित गतिविधियां भी शामिल हैं। सर्दियों में तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इस स्थिति के लिए 93 फीसद तक मानव गतिविधियां ही जिम्मेदार होती हैं। आइआइटी कानपुर, दिल्ली और पुणे (दिल्ली शाखा) के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार संयुक्त रिसर्च पेपर में यह बात कही गई है। (पेज-2)

टेलीकॉम कंपनियों ने डेढ़ गुना किया टैरिफ

नई दिल्ली, प्रेट्र : टेलीकॉम सेक्टर की प्रतिस्पर्धा और कंपनियों की देनदारी का बोझ अब ग्राहकों के कंधे पर आने वाला है। विभिन्न मदों में करीब 80 हजार करोड़ रुपये की देनदारी चुकाने की कोशिश में जुटी टेलीकॉम कंपनियों वोडाफोन-आइडिया और एयरटेल ने अपने कॉल और डाटा टैरिफ में 50 फीसद तक की वृद्धि का एलान कर दिया है। बढ़ी हुई दरें दो-तीन दिसंबर की दरम्यानी रात से लागू होंगी। रिलायंस जियो ने भी दरों में 40 फीसद तक की वृद्धि की बात कही है।

रविवार को वोडाफोन-आइडिया ने टैरिफ में बढ़ोतरी का एलान किया। इसके बाद एयरटेल और रिलायंस जियो ने भी इस दिशा में कदम बढ़ा दिया। वोडा-आइडिया और एयरटेल ने कॉल-डाटा टैरिफ में 50 फीसद तक की बढ़ोतरी की है। सबसे ज्यादा 50 फीसद की वृद्धि सालभर के अनलिमिटेड पैक पर की गई है। वोडा-आइडिया में पहले 999 रुपये में 12 जीबी डाटा के साथ सालभर की वैधता मिलती थी। अब इस पैक की कीमत 24 जीबी डाटा के साथ 1499 रुपये हो गई है। एयरटेल में पहले यह पैक 998 रुपये का था। अब एयरटेल भी इस पैक के लिए 1499 रुपये वसूलेगी। इसी तरह वोडा-आइडिया ने सालभर तक प्रतिदिन डेढ़ जीबी डाटा वाला अनलिमिटेड पैक 1699 से बढ़ाकर 2399 रुपये कर दिया है। एयरटेल इसके लिए 2398 रुपये वसूलेगी। अन्य छोटी-बड़ी अवधि वाले पैक में भी बढ़ोतरी की गई है। जियो ने टैरिफ में 40 फीसद तक वृद्धि करने का एलान किया है। जियो की बढ़ी हुई दर छह दिसंबर से प्रभावी होगी।

- तीन दिसंबर से बढ़ जाएगा कॉल और डाटा का खर्च
- वोडा-आइडिया, एयरटेल और जियो ने किया एलान
- ग्राहकों पर पड़ेगा कंपनियों की देनदारियों का बोझ

प्रतीकात्मक

कम से कम 49 रुपये का खर्च

टैरिफ वृद्धि के बाद वोडा-आइडिया और एयरटेल दोनों ही कंपनियों ने 28 दिन की वैलिडिटी के लिए न्यूनतम मासिक शुल्क 49 रुपये कर दिया है। पहले यह पैक 23 रुपये का था। इसका अर्थ है कि एयरटेल या वोडा आइडिया के किसी नंबर को इस्तेमाल करते रहने के लिए आपको न्यूनतम 49 रुपये मासिक का रिचार्ज कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर उस नंबर की इनकमिंग भी बंद हो जाएगी।

अनलिमिटेड के दावे से बचना जरूरी

पैक में बदलाव के बाद ग्राहकों को कंपनियों के अनलिमिटेड कॉल के दावे से भी सतर्क रहना होगा। वोडा-आइडिया और एयरटेल ने सभी पैक में अपने नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर की जाने वाली कॉल को सीमित कर दिया है। 28 दिन के पैक पर 1000 मिनट, 84 दिन के पैक पर 3000 मिनट और 365 दिन के पैक पर 12000 मिनट की कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। इसके ऊपर छह पैसे प्रति मिनट का भुगतान करना होगा। समान नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलेगी।

दबाव से जूझ रही हैं टेलीकॉम कंपनियां

2016 में टेलीकॉम सेक्टर में मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस जियो के उतरने के बाद कॉल और डाटा की कीमतों में तेज गिरावट आई थी। एक जीबी 4जी डाटा के बदले 250 से 400 रुपये तक वसूल रही टेलीकॉम कंपनियों को जियो के सामने प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए अपने टैरिफ में बड़ी कटौती करनी पड़ी थी। तब से कंपनियां घाटे में चल रही हैं। एजीआर पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद वोडा-आइडिया की देनदारी करीब 44150 करोड़ रुपये हो गई है। एयरटेल की देनदारी करीब 35586 करोड़ रुपये है। दोनों कंपनियों को पिछली तिमाही में जबर्दस्त गिरावट का सामना करना पड़ा है।

गोरखपुर में स्कूल परिसर में जनाजे की नमाज, बाधित हो रही पढ़ाई

जागरण संवाददाता, गोरखपुर

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के प्राथमिक विद्यालय बड़गो खोराबार में मुस्लिम समुदाय के लोग जनाजे की नमाज पढ़ते हैं। इस दौरान छात्रों को कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, ताकि विवाद उत्पन्न न हो। रविवार को सूचना पर जिलाधिकारी ने इसके विकल्प की तलाश के लिए तहसीलदार को मौके पर भेजा।

बड़गो खोराबार विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजेश धर दूबे ने बताया कि यह अंग्रेजी माध्यम विद्यालय 1965 में बना था। इसके पहले यहां खाली मैदान हुआ करता था। यहां एक पीपल का पेड़ है, जहां हिंदू परिवार के सदस्य की मौत होने पर घंट बांधने आते हैं और कर्मकांड करते हैं, जबकि मुस्लिम शव रखकर जनाजे की नमाज पढ़ते हैं। अब विद्यालय में चहारदीवारी बन गई है। बावजूद इसके यह क्रम जारी है। उन्होंने कहा कि समस्या तब आती है जब जनाजे की नमाज के दौरान लोग परिसर में आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब तक उनकी नमाज चलती है बच्चों को कमरे के अंदर रखना पड़ता है, ताकि हल्ला-गुल्ला न करें। राजेश धर दूबे ने कहा, ऐसी स्थिति में कक्षाओं में पढ़ाई भी बाधित होती है। यदि इसका विकल्प मिल जाता तो बेहतर होता।

- सूचना पर जिलाधिकारी ने तहसीलदार को भेजा, बीएसए स्वयं तलाशेंगे विकल्प

> जानकारी मिली है। मैं स्वयं मौके पर जाकर देखूंगा। सौहार्दपूर्ण वातावरण में दोनों पक्षों से बात कर विकल्प की तलाश की जाएगी, जिससे छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो। -भूपेंद्र नारायण सिंह, बीएसए

हिंदुत्व की विचारधारा को कभी नहीं छोड़ूंगा : उद्धव

राज्य ब्यूरो, मुंबई

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रविवार को विधानसभा में एलान किया कि वह हिंदुत्व की विचारधारा को कभी नहीं छोड़ेंगे। उद्धव का यह बयान महाविकास अघाड़ी के घटक कांग्रेस और राकांपा के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, जिन्होंने शिवसेना के साथ राज्य में गठबंधन सरकार बनाई है। यही नहीं, सरकार चलाने के लिए तीनों दलों के बीच बने न्यूनतम साझा कार्यक्रम (सीएमपी) की भूमिका में ही खासकर 'सेक्यूलर' शब्द का उल्लेख किया गया है। विधानसभा सत्र को 16 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, 'मैं अभी भी हिंदुत्व की विचारधारा के साथ हूं, इसे मुझसे अलग नहीं किया जा सकता है।' पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस पर कटाक्ष करते हुए ठाकरे ने कहा, 'दिए गए वचन का पालन करना ही मेरे हिंदुत्व का हिस्सा है। जय श्री राम बोलना एवं वचन का पालन न करना हिंदुत्व नहीं है। मैं कल भी अपने हिंदुत्व का पालन करता था, आज भी करता हूं और आगे भी करता रहूंगा।' ठाकरे का इशारा फड़नवीस के उस बयान की तरफ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा ने कभी सीएम पद को साझा करने का वादा नहीं किया था।

बाद में पत्रकारों से बातचीत में ठाकरे ने कहा कि आरे कालोनी में मेट्रो रेल कारशेड के निर्माण कार्य के विरोध के दौरान लोगों पर दर्ज केस वापस लिए जाएंगे। उन्होंने आदेश दे दिया है।

उद्धव का फड़नवीस पर कटाक्ष पेज>>4

- राकांपा और कांग्रेस को असमंजस में डाल सकता है ठाकरे का बयान
- आरे कालोनी मामले में लोगों पर दर्ज हुए केस वापस लेगी सरकार

मुंबई में रविवार को पत्रकारों के सवालों का जवाब देते महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे। एएनआइ

कांग्रेस के विधायक नाना पटोले निर्विरोध स्पीकर निर्वाचित

भाजपा द्वारा अपने प्रत्याशी का नाम वापस ले लेने के बाद कांग्रेस के नाना पटोले विधानसभा के निर्विरोध अध्यक्ष (स्पीकर) चुन लिए गए। भाजपा की ओर से किशन कठोरे उम्मीदवार थे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने आज यह कहते हुए अपने दल का उम्मीदवार वापस ले लिया कि महाराष्ट्र में विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की परंपरा नहीं रही है।

फड़नवीस नेता प्रतिपक्ष बने

विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद नाना पटोले ने भाजपा नेता फड़नवीस को नेता प्रतिपक्ष घोषित किया। उन्होंने फड़नवीस पर कटाक्ष करते हुए यह भी कहा कि जो लोग विपक्ष चाहते ही नहीं थे, उनके साथ उचित न्याय हुआ है कि अब वह स्वयं एक प्रभावी विपक्ष की भूमिका में नजर आएंगे।

हैदराबाद कांड का साया

लालकिला मैदान पर आयोजित गीता प्रेरणा महोत्सव पर दिखा हैदराबाद की घटना का साया, भागवत ने कहा, घर से शुरू हो मातृशक्ति के सम्मान की शिक्षा, राजनीतिज्ञों से लेकर साधु-संत तक दिखे मर्माहत

गीता महोत्सव के मंच से नारी सम्मान की चिंता

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

हैदराबाद में पशु चिकित्सक से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की हृदयविदारक घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। यहां लालकिला मैदान पर आयोजित गीता प्रेरणा महोत्सव में जुटे लोग इससे मर्माहत दिखे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि मातृशक्ति के प्रति सम्मान की शिक्षा हमें घर से ही शुरू करनी होगी। ऐसा अपराध करने वालों की भी बहन और माता हैं। ऐसे लोगों को शायद घर में किसी ने सिखाया नहीं कि मातृशक्ति से कैसे व्यवहार करना चाहिए।

जीयो गीता संस्थान की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में भागवत ने महाभारत के एक प्रसंग का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब अर्जुन के सामने उर्वशी खड़ी थीं, तो वह उन्हें एकटक देख रहे थे। बाद में उर्वशी ने कहा कि तुम मुझे पसंद करते हो, इसलिए देख रहे हो, तब अर्जुन कहते हैं कि आप हमारी पूर्वज हैं, माता के समान हैं। इसलिए मातृभाव से देख रहा था। समाज में भी जब यही भाव होगा तो देश में मातृशक्ति का सम्मान और सुरक्षा अपने आप हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की है और रहेगी। लेकिन, सबकुछ उन्हीं पर छोड़ देने से नहीं चलेगा। इसके लिए परिवार को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। इसके साथ ही उन्होंने गीता को जीवन का सार बताते हुए कहा कि इसे संपूर्ण विश्व का बनाने के लिए शुरुआत खुद से करनी होगी। 130 करोड़ की जनता को इसे हर घर और गांव तक पहुंचाना होगा।

साध्वी ऋतंभरा ने कहा कि पुरुष जब काम वासना का पुतला बनेगा तो घर की बहू-बेटियां भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। भारत जैसे देश में दुष्कर्म और भ्रष्टाचार अशोभनीय व चिंताजनक है। अखिल भारतीय इमाम संगठन के मुख्य इमाम डॉ. उमर अहमद इलयासी ने कहा कि हैदराबाद की घटना के आरोपितों को सरेआम फांसी होनी चाहिए। जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि ने कहा कि गीता को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, जिससे इस तरह के कुसंस्कारी पैदा न हों। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गीता को वैश्विक धरोहर बताते हुए कहा, इसमें हर चुनौती और समस्या का समाधान समाहित है। महोत्सव में उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश पढ़ा। इसके साथ ही मध्यम एवं लघु उद्योग राज्य मंत्री प्रताप चंद सारंगी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जनार्दन द्विवेदी, अवधेशानंद महाराज, परमानंद महाराज, राघवानंद महाराज, स्वामी ज्ञानानंद, विवेक मुनि समेत अन्य ने महोत्सव को संबोधित किया।

नई दिल्ली के लालकिला मैदान में आयोजित गीता प्रेरणा महोत्सव को संबोधित करते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत। जागरण

> मातृशक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की है और रहेगी, लेकिन, सब कुछ उन्हीं पर छोड़ देने से नहीं चलेगा। इसके लिए परिवार को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। -मोहन भागवत, सरसंघ चालक

साधु-संत भी करें समाज को जागरूक : स्मृति ईरानी

महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने महिला सुरक्षा को लेकर समाज को जागरूक करने के लिए साधु-संतों को आगे आने का आह्वान किया। महिलाओं का सम्मान और उनका संरक्षण न सिर्फ हमारा कर्तव्य है, बल्कि इसे धर्म स्वयं परिभाषित करता है। ऐसे में आग्रह है कि संत चरण जहां-जहां पड़ें, इसका उच्चारण विशेष रूप से करें। उन्होंने नवजात और गर्भवती महिलाओं में कुपोषण के प्रति भी सबको जागरूक करने का आग्रह किया।

स्मृति ईरानी फाइल फोटो

करतारपुर पर पाक की साजिश बेपर्दा, इमरान से सतर्क रहें सिद्धू : कैप्टन

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख राशिद द्वारा करतारपुर कॉरिडोर पर दिए हालिया बयान से पाक सेना की साजिश बेपर्दा हो गई है। उन्होंने अपने पूर्व कैबिनेट सहयोगी नवजोत सिद्धू को सलाह दी है कि वह इमरान खान से दोस्ती और पाक सरकार से मिलने वाले मौकों को लेकर सतर्क रहें। दोस्ती का किसी फैसले पर प्रभाव न पड़ने दें। यह भारत के लिए घातक होगा।

कैप्टन ने कहा, उनकी इस आशंका की पुष्टि हो गई है कि करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा के दिमाग की उपज है। बाजवा ने जब सिद्धू से कॉरिडोर के निर्माण संबंधी फैसले की बात कही थी तब इमरान ने पद भी नहीं संभाला था। यह कैसे संभव है कि कॉरिडोर के फैसले के पीछे बाजवा नहीं था। इसलिए सिद्धू को ज्यादा सचेत रहना चाहिए।

कैप्टन ने राशिद के इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई कि कॉरिडोर भारत को नुकसान पहुंचाएगा और इसके माध्यम से बाजवा द्वारा दिए घाव को भारत हमेशा याद रखेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, भारत को उम्मीद थी कि यह कॉरिडोर दोनों देशों के बीच शांति के लिए पुल का काम करेगा, लेकिन राशिद का बयान भारत की सुरक्षा व अखंडता के लिए गंभीर खतरा है। पाकिस्तान गलतफहमी पैदा करने का प्रयास न करे, अन्यथा उसे गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

करतारपुर कॉरिडोर को पहले भी आइएसआइ का एजेंडा बता चुके कैप्टन ने कहा कि वह हमेशा यही कहते आए हैं कि एक सिख होने के नाते कॉरिडोर खुलने की उनको बहुत खुशी हुई है, लेकिन इससे हमारे देश को संभावित खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगाह किया कि कॉरिडोर के द्वारा पाकिस्तान सिखों का दिल जीतने की कोशिश कर रहा है। जिससे आइएसआइ के इशारे पर काम करने वाले सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) द्वारा रेफरेंडम-2020 के एजेंडे को आगे बढ़ाया जा सके। उल्लेखनीय है कि एसएफजे खालिस्तान समर्थक संगठन है।